



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्रतिभक्तर से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9]
No. 9]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 8, 1985/वीष 18, 1906
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 8, 1985/PAUSA 18, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

विधि और न्याय मंत्रालय
(न्याय विभाग)

सकल्प

नई दिल्ली 5 जनवरी 1985

सं० 46/4/81-न्याय—यत उत्तर प्रदेश के पश्चिम जिलों के लिए
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक बेंच की स्थापना की मांग से उत्पन्न
मर्मों, पहलुओं पर तथा राज्य सरकार द्वारा की गई सिफारिशों के
विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए भारत सरकार ने अपने
तारख 4 मिनम्बर, 1981 के सकल्प सं० 46/2/81-न्याय के तहत
भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश, श्री जसवंतसिंह
की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था

और यत गोहाटी, कर्नाटक मध्य प्रदेश और मद्रास न्यायालयों की
बैंचों के मूल स्थानों से हटकर स्थानों पर स्थापित करने और उच्च
न्यायालयों के मूल स्थानों के हटकर स्थानों पर बैंचों की स्थापना करने
के सामान्य प्रश्न के संबंध में पहलुओं की श्री जांच करने और रिपोर्ट
देने और इस संबंध में अपनाए जाने वाले व्यापक सिद्धांतों और मापदंडों
तथा विशेषकर पूर्वोक्त उच्च न्यायालयों की स्थायी बैंचों की स्थापना
की मांगों की जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए भारत सरकार ने
अपने तारख 14 दिसम्बर, 1983 के सकल्प सं० 46/2/81-न्याय के

तहत भारत सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की गई मांगों
का विचार करने के लिए आयोग में भेजा गया था

और, यत आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने का निर्धारित
समय समाप्त हो गया है और आयोग ने समय बड़ाए जाने की मांग
की है

अतः भारत सरकार ने आयोग द्वारा अपने रिपोर्ट प्रस्तुत
किए जाने का समय मार्च, 1985 के 14 तारख तक जिसमें यह
तारख भी शामिल है बढ़ाने का निर्णय किया है।

तदनुसार आयोग मार्च, 1985 का 13 तारख को या इससे पहले
अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा।

मन्त्र विह उप मन्त्रि

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Department of Justice)

RESOLUTION

New Delhi, the 5th January, 1985

F. No. 46/2/81-Jus.—Whereas the Government of
India vide its Resolution No. 46/2/81-Jus dated the

4th September, 1981 had set up a Commission with Shri Jaswant Singh, Retired Judge, Supreme Court of India as Chairman, to consider all aspects arising out of the demand for the constitution of a Bench of the Allahabad High Court for the Western districts of Uttar Pradesh and the various aspects of the recommendations made by the State Government;

And whereas, the Government of India vide its Resolution No. J6/2/81-Jus dated the 14th December, 1983 required the Commission to consider the demands made by the State Governments concerned for the establishment of Benches of the High Courts of Gauhati, Karnataka, Madhya Pradesh and Madras at places other than their principal seats and also to examine and report on all aspects of the general question of having Benches of High Courts at places

other than their principal seats and on the broad principles and criteria to be followed in this regard and in particular on the demands for the establishment of the permanent Benches of the High Courts aforesaid;

And, whereas, the time fixed for submission of the report by the Commission has expired and the Commission has asked for extension of time.

Now, therefore, the Government of India have resolved to extend the time for submission of its report by the Commission upto and inclusive of the 13th day of March, 1985.

2. The Commission will accordingly submit its report on or before the 13th day of March, 1985.

SURENDRA SINGH, Dy. Secy.